



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1023]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2015/वैशाख 25, 1937

No. 1023]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2015/VAISAKHA 25, 1937

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 मई, 2015

का.आ. 1304(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3235(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2014, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 18 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में, या उस पर के अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यांतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गयी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए तैयार है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उस पर के सभी अधिकार, तारीख 18 दिसम्बर, 2014 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :—

- (1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसान और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;
- (2) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त कंपनी द्वारा वहन

किये जाएंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार के लिए या उसके संबंध में जैसे अपील आदि की सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, इसी प्रकार उक्त कंपनी द्वारा वहन किये जाएंगे;

- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, प्रतिपूर्ति करेंगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
- (4) सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और भूमि में या उसके ऊपर इस प्रकार निहित अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किये जाएं, पालन करेगी।

[फा. सं. 43015/7/2012-पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi, the 11th May, 2015

S.O. 1304(E).—Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 3235(E), dated the 17th December, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th December, 2014 issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the Northern Coalfields Limited, Singrauli, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby direct that the said land and all rights in or over the said land so vested shall with effect from the 18th December, 2014 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (1) The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;
- (2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under condition (1), and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals etc., for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vesting, shall also be borne by the Government Company;
- (3) The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;
- (4) The Government Company shall have no power to transfer the said lands to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
- (5) The Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land as and when necessary.

[F. No. 43015/7/2012- PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.